नई सोच, नया आयाम

जोहार छत्तीसगढ़

RNI No. CHHHIN/2009/35020

दैनिक हिन्दी

◆ वर्ष: -14 ◆ अंक: 183 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 ◆ मूल्य: 2 ₹ ◆ पृष्ठ : 4

धरमजयगढ़, मंगलवार 10 मई 2022

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

पेज -3 पर

सहकारी समितियों में अनाधिकृत रूप से झाइम खाद की बिक्री ...

बारंगाव की उभरती खिलाड़ी डाली का नेशनल हाकी प्रतियोगिता के लिए ....

पेज -4 पर

एक नजर

व्यापारी ने गिरा दिया 25 लाख रुपयों से भरा बैग

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक व्यापारी को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बैंक में जमा करने के लिए ले जा रहे 25 लाख रुपयों से भरा बैग रास्ते में गिर गया। इसका व्यापारी को पता ही नहीं चला। जब बात पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। इस दौरान बाजार में लगे CCTV में बाइक सवार महिला और पुरुष बैग उठाकर जाते हुए दिखाई दिए। अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। मामला बालोद कोतवाली क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व उपाध्यक्ष और शहर के बड़े होलसेल किराना व्यापारी ताराचंद सांखला का बेटा समकित सोमवार को बैग में रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पुराना बस स्टैंड के पास बैग गिर गया। समकित को इसका पता ही नहीं चला। जब बैंक पहुंचने पर बैग नहीं मिला तो समकित तलाश करने निकले, लेकिन नहीं मिला। इस पर उन्होंने अपने पिता और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद SP, एडिशनल SP और थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जांच शुरू की गई तो एक दुकान में CCTV लगा मिल गया। उसे चेक करने पर दिखाई दिया कि बैग सड़क पर पड़ा था।

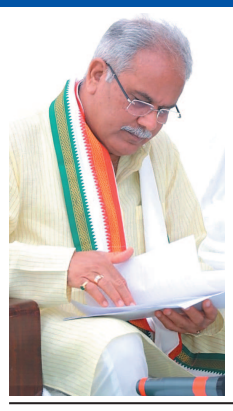

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी शिकायत नहीं मिली : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात अभियान के छठवें दिन सूरजपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है, राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हों। वन अधिकार का पट्टा वितरण में यह ध्यान रखें कि हितग्राहियों को वास्तविक कब्जा पर पट्टा मिले। यह भी सावधानी रखें कि वास्तविक हितग्राही को ही 'वन अधिकार पट्टा वितरित किया जाए। इस अवसर पर विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खेलसाय सिंह, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान 6 दिनों में सरगुजा संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्रों सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर में 20 स्थानों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि नरवा योजना का लाभ मैदानी स्तर पर दिख रहा है। नरवा प्रोजेक्ट में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में काम सुधारने की जरूरत है।

गोधन न्याय योजना में खरीदी से लेकर राशि वितरण तक की प्रक्रिया में सब ठीक

गौठान में स्व सहायता समूह कर रहे हैं अच्छा काम

आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सभी जगह हो रही है तारीफ

राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हों

दाऊद के करीबियों पर एनआईए के छापे

माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी समेत तीन हिरासत में, इनमें छोटा शकील का साला भी

मुंबई। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी, यानी NIA ने रेड की है। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एक्शन जारी है। इसके दायरे में दाऊद का गुर्गा छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े लोग और उसके रिश्तेदार शामिल हैं। रेड के दौरान NIA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माहिम और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहैल खंडवानी को कस्टडी में लिया है। सुहैल खंडवानी टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी 2006-2016 तक उसी फर्म में निदेशक थे। इस कंपनी में फराज के अलावा, फारूक और जकारिया दरवेश भी पार्टनर हैं। NIA की टीम इनसे भी पूछताछ कर सकती है। फराज को छोड़कर सभी एसोसिएट हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी के बोर्ड में भी हैं। 150 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सीबीआई द्वारा इस फर्म की भी जांच की जा रही है। टीम मुंबई के गोवा वाला कंपाउंड में रेड कर रही है। इसी जगह पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का घर है। मलिक को दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

कौन है सलीम फ्रूट

सलीम फ्रूट छोटा शकील का साला है। शकील अपने गुर्गों के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है। सलीम फ्रूट को 2006 में UAE से भारत डिपोर्ट गया था और 2010 से जेल में बंद है। उसे वहीं से अरेस्ट किया गया। सलीम फ्रूट के अलावा दाऊद इब्राहिम के साले सऊद युसुफ तुंगेकर, दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के साथी खालिद उस्मान शेख और दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे आलीशान पारकर का बयान भी दर्ज किया जा सकता है।

फरवरी में D-कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ

फरवरी में गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया था, उस मामले में ही यह छापेमारी चल रही है। आरोप है कि ये लोग एक्सटॉर्शन मनी का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करते हैं। NIA ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, यानी UAPA के तहत केस दर्ज किया है। इन सबका कनेक्शन 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम से बताया जा रहा है।

रायपुर में बड़े प्रदर्शनों पर रोक

रायपुर। लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देकर रायपुर जिला प्रशासन ने अब बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बड़े प्रदर्शन के लिए रोक लगा दी है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब केवल 100 की संख्या में ही प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकेंगे।

इसके लिए भी प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बड़े प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में पुराने राज्योत्सव के सामने मैदान को नया धरना स्थल निर्धारित किया गया है। रायपुर जिला प्रशासन का कहना है, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन और स्थानीय पार्षद सहित आमजनो ने भी बूढ़ा तालाब धरना स्थल को अन्यत्र स्थनांतरित करने की मांग की थी। उनका कहना था, यहां भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया, जन भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहर के इस बूढ़ा तालाब के सामने के धरना स्थल को नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने हर तरह के प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजन से पूर्व प्रशासन ने अनुमति लेना अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के साथ आवेदन का प्रारूप भी था, जिसकी शर्तों के मुताबिक ही किसी आयोजन की अनुमति दी जानी है। विपक्ष इस निर्देश का विरोध कर रहा है। इसके लिए भाजपा ने 16 मई को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

जन भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहर के इस बूढा तालाब के सामने के धरना स्थल को नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने स्थानांतरित किया जा रहा है।

सौरभ कुमार, कलेक्टर, रायपुर

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नया सेटअप

किसी हाईस्कूल में 220 से कम स्टूडेंट हुए तो संस्कृत टीचर नहीं मिलेगा

प्राइमरी स्कूलों में केवल तीन अध्यापक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का नया सेटअप तैयार किया है। इसमें दर्ज संख्या को शिक्षकों की नियुक्ति का आधार माना गया है।

बताया जा रहा है, नए सेटअप के मुताबिक हाईस्कूल में 220 से कम विद्यार्थी हुए तो वहां एक प्राचार्य और पांच अध्यापक ही मिलेंगे। वहां संस्कृत शिक्षक का पद नहीं होगा। 80 से कम विद्यार्थियों वाले प्राथमिक स्कूल में एक प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षक ही मिलेंगे।

नए सेटअप के मुताबिक प्राथमिक स्कलों की दर्ज संख्या में क्रमश: 30 विद्यार्थियों की वृद्धि पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। मिडिल स्कूल में 6 वीं से 8 वीं तक के सेटअप में एक प्रधानपाठक और 4 शिक्षक के पद स्वीकृत किए हैं। मिडिल स्कूल में 30 से कम विद्यार्थी हुए तो वहां प्रधानपाठक का पद भी नहीं होगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं यानी कक्षा 9वीं से 12 वीं तक के सेटअप में 1 प्राचार्य सहित 9 व्याख्याता के पद स्वीकृत किए गए हैं।

धूप की आंच हुई तेज, तापमान 43.23 सेल्सियस पर

कोरबा । दो दिनों तक तापमान कम रहने के बाद फिर तेज हो गया। तेज धूप के साथ लू का असर होने से यात्री दोपहर को हलकान रहे। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच लोगों को अब बेसब्री से मानसून का इंतजार होने लगा है। सूर्योदय के बाद धूप का असर तेज होने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। दो दिन पहले शहर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस में थम गया था। रविवार को सुबह से ही आसमान साफ होने से गर्मी का असर पूरे दिन अधिक रहा। दोपहर आते तक तापमान 43.23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में औचक वृद्धि से राहगीर हलकान रहे। अनुमान लगाया जा रहा था कि दोपहर के बाद अन्य दिनों की तरह तेज हवा के साथ बदली होगी।

रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ऐसा भी फोकस

विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के घर लगाया नेमप्लेट, ऐसा 3000 घरों पर लगेगा

रायपुर। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं पर फोकस किया है। विधायक ने अपने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर नेमप्लेट लगा रहे हैं। इस पर कार्यकर्ता का नाम, वार्ड का नाम के साथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी लगा हुआ है। विधायक विकास उपाध्याय ने संत रविदास वार्ड और ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड में जनसंपर्क किया। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के तौर पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत उन्होंने सहदेव नायक, भरथरी निषाद आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं के घर पर खुद नेम प्लेट लगाया। इस दौरान उन्होंने अपने नेताओं के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं के जिंदाबाद का भी नारा लगाया। इस अभियान के बारे में विकास उपाध्याय ने बताया, अपने क्षेत्र में इन दिनों वे सोनिया गांधी जन संपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय जनता से मुलाकात हो रही है। उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने की कोशिश हो रही है। उनकी मांगों के अनुरूप काम करने की बात हो रही है। इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मैंने तय किया है कि वार्ड में कांग्रेस के खांटी और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसे नेम प्लेट लगाउंगा।

33 ट्रेनें रद्द होने से यात्री हो रहे हलाकान

रायपुर । पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु के सीजन में यात्री भाड़े से सर्वाधिक कमाई करने वाला इंडियन रेलवे मिली जानकारी के अनुसार कोयले की कमी के चलते बिजली संकट के चलते माल ढुलाई ट्रेनों को ही चला पाने की स्थिति में है। देश के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय रेल को बिना किसी मुनासिब कारण से 33 ट्रेनें एक साथ रद्द करनी पड़ी है। ज्ञातव्य है कि गर्मी की छुट्टी में ज्यादातर लोग शादी विवाह, रिश्तेदारी एवं पर्यटन के उद्देश्य से घूमने निकलते हैं। वहीं उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम रेलवे मुंबई, दिल्ली, हावड़ा सहित अनेक राज्यों में टिकटों की मारामारी के चलते यात्री जबर्दस्त भीड़ के चलते हलाकान हो रहे हैं।

कार्यवाही... सरगुजा दौरा बीच में छोड़कर सीएम भूपेश दिल्ली रवाना

हेलीकॉप्टर टेकऑफ होते ही सूरजपुर सीईओ को हटाने का आदेश

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मई को प्रस्तावित सरगुजा दौरा बीच में स्थगित कर दिल्ली रवाना हो गए। वे कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। सीएम का सोमवार को सरगुजा के लुंड्रा क्षेत्र में दौरा एवं अंबिकापुर में बैठक का कार्यक्रम था।

सूरजपुर में सुबह समीक्षा बैठक लेने के बाद सीएम रायपुर रवाना हो गए। इधर मुख्यमंत्री बघेल का हेलीकॉप्टर टेकऑफ होते ही सूरजपुर जिला पंचायत के सीईओ को हटाने का आदेश जारी हो गया है। बता दें कि प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने सीएम भूपेश बघेल का दौरा 4 मई से सरगुजा संभाग से शुरू हुआ है। रविवार को सीएम ने सूरजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर सूरजपुर में रात्रि विश्राम किया। सोमवार सुबह उन्होंने सूरजपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और रायपुर के लिए रवाना हो गए। आज अंबिकापुर में समीक्षा बैठक लेने के साथ ही लुंड्रा क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रायपुर से फ्लाइट द्वारा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वे दिल्ली पहुंच शाम को कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी द्वारा बुलाए गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 13 से 15 मई तक उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर एवं वर्ष 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। यह बैठक छत्तीसगढ़ के हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

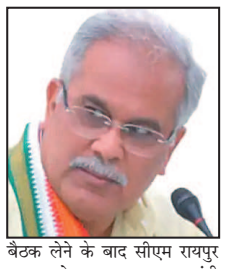

मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचेंगे दिल्ली

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामानांतर अपना दौरा कार्यक्रम शुरू करने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अपना कार्यक्रम अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव व पीसीसी चीफ के दिल्ली दौरा को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गरमा गई है।

सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को हटाया

सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार सुबह सूरजपुर में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान न्याय योजना में कहीं शिकायत नहीं मिली है, लेकिन राजस्व अमले को जमीनी स्तर पर कार्य में सुधार की जरूरत है। गोठान योजना एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीएम खुश नहीं दिखे।

लोहे सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर ठेकेदारों ने हाथ खड़े किए

रायपुर । सीमेंट और लोहा की बढ़ती कीमतों ने सभी सरकारी कंस्ट्रक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। इससे सबसे ज्यादा आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग, एनआरडीए, आरडीए, नगर निगम, वन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ठेकेदारों ने एकजुट होकर सभी शासकीय कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर दिए हैं। इससे सालों लेट चल रहे निर्माण कामों को पूरा होने में और देरी हो रही है।

टेंडर लेने के समय और अभी की स्थिति में मटेरियल की कीमतों में 50 से 60 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वजह से सरकारी ठेकेदारों ने निर्माण काम बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि अभी काम किया तो उन्हें कई गुना नुकसान होगा। इसलिए सभी विभागों के ठेकेदारों ने एकजुट होकर काम बंद कर दिया। सरकारी ठेकेदारों का कहना है कि विभाग ने जब रेट दिया था उस समय सीमेंट और लोहा की कीमत कम थी, लेकिन अभी उसमें 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में पुराने टेंडर रेट में किसी भी परिस्थिति में काम करना मुश्किल है।

आरोप-प्रत्यारोप का दौरः राजनेताओं और नौकरशाहों का मिटता फर्क

बिना किसी रोक-टोक के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना आम तौर पर राजनेताओं की आदतों में शुमार है, जिनके प्रतिनिधि हर दिन टीवी पर प्राइम टाइम बहस में और ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया पर लड़ते रहते हैं। अफसोस कि इस बीमारी ने सेवानिवृत्त नौकरशाहों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सेवानिवृत्ति के बाद सिविल सेवक सामान्य नागरिकों की स्थिति में लौट आते हैं।

इसलिए उनके द्वारा अपने विचारों को सार्वजनिक रूप में प्रकट करने को गलत नहीं बताया जा सकता, जिन्हें उन्होंने सेवा आचरण नियमों के कारण दशकों से दबा रखा था। और राष्ट्र के सामान्य, पर प्रबुद्ध नागरिकों के रूप में, उन्हें भी सरकार की नीतियों और निर्णयों की प्रशंसा व समर्थन करने या आलोचना करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देशों में यह सामान्य घटना है।

अगर कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों को लगता है कि प्रधानमंत्री देश के महत्वपूर्ण हितों की सेवा कर रहे हैं, अपने अंतरराष्ट्रीय कद को ऊंचा कर रहे हैं और भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं, तो उन्हें इसे बताने का अधिकार है। यह बात किसी को क्यों खटकनी चाहिए? उसी तरह से यदि कुछ पूर्व नौकरशाहों को लगता है कि जैसा दावा किया गया था, चीजें वैसी नहीं हैं और जनहित के कई बड़े मुद्दे अनसुने रह गए और सरकार ठोस परिणामों के बजाय प्रचार और तीखी बयानबाजी में उलझी रह गई, तो उन्हें भी अधिकार है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सरकार की आलोचना के कारण उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों उठना चाहिए? क्या हम इतने असुरक्षित हैं? स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ आलोचना जरूरी है। लेकिन क्या निराधार और असंतुलित आलोचना को रचनात्मक माना जा सकता है? हिंसा चाहे जिसने भी शुरू की हो, उसकी आलोचना की जानी चाहिए और असली अपराधियों को जितनी जल्दी हो, कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने, कार्टून बनाने या स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में मजाक करने जैसे तुच्छ आधारों पर गिरफ्तारी लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। इसी

भाजपा के पास सरकार का बचाव करने के लिए मुखर प्रवक्ता हैं। फिर कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाह किस वजह से अपनी ही बिरादरी के सदस्यों पर हमला करते हैं? क्या यह नेशनल टीवी पर कुछ देर जगह पाने का लालच है।

तरह से गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग या सुरक्षा बलों की ज्यादती पर ध्यान आकर्षित करना अपराध नहीं है। बल्कि जनहित में ऐसी घटनाओं को सरकार के समक्ष लाना प्रत्येक विवेकशील नागरिक का कर्तव्य है। नागरिकों को क्या खाना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, इसके बारे में निर्देश देना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है! अलबत्ता इन सबके लिए प्रधानमंत्री को दोष देना कितना सही है? देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही कुछ नकारात्मक घटनाओं के बावजूद क्या प्रधानमंत्री को हिटलर कहने और उन पर फासीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाने का कोई मतलब है? उनके आलोचकों को संतुलन नहीं खोना चाहिए।

नेक इरादे से भी की गई आलोचना में संतुलन की कमी अक्सर उसकी विश्वसनीयता खत्म कर देती है। हां, 1.3 अरब से अधिक लोगों की सरकार के मुखिया होने के नाते जब ऐसी चीजें होती हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी घटनाओं की त्वरित, मजबूत और स्पष्ट निंदा और शांति व सद्भाव की अपील स्थिति को नियंत्रण में ला सकती है। हाल ही में मैं कुछ सिविल सेवकों को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर अपने साथी नौकरशाहों/महिलाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए देखकर चकित था। उनमें से कुछ 10-15 वर्ष वरिष्ठ हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं। उनका आरोप था कि सरकार की आलोचना करने वाले पूर्व नौकरशाह किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर काम कर रहे होंगे! यह कितना हास्यास्पद तर्क है!

उनकी और जो भी कमियां रही हों, यह तो मानना पड़ेगा कि नौकरशाहों ने इस देश को एकजुट रखा है और कुछ बुरे लोगों को छोड़कर उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है और अपने राजनीतिक आकाओं को सर्वोत्तम संभव सलाह दी है। यदि यह सच नहीं होता, तो ऐसे नौकरशाह नहीं होते, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के चार-पांच प्रधानमंत्रियों के अधीन कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव और विदेश सचिव के रूप में कार्य कर चुके होते! जो कभी कैबिनेट सचिव या विदेश सचिव या विभिन्न मंत्रालयों में सचिव और बड़े राज्यों में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य करते थे, उन पर यह आरोप लगाना बेतुका है कि वे विदेशी शक्तियों के लिए कार्य कर सकते हैं। यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आरोप जैसा है कि अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहता था!

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य, जो तीन प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी हैं, 40 वर्षों तक भारतीय विदेश सेवा के सदस्य रहे और उन्होंने 11 प्रधानमंत्रियों के साथ सेवा की। उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, योग्यता और व्यावसायिकता पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। अन्य सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए इससे अलग तथ्य क्यों होना चाहिए?

सुरेंद्र कुमार

संपादकीय

झारखंड कांग्रेस की पालकी ढोने की मजबूरी

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। कांग्रेस के 16 जीते हुए विधायक हैं और दो विधायक बाबूलाल मरांडी की पार्टी छोड़ कर आए थे, जिनमें से एक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म हो गई है। फिर भी कांग्रेस के 17 विधायक हैं और इसके दम पर कांग्रेस को कमांडिंग पोजिशन में होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार में कोई महत्व नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी सरकार की पालकी ढो रही है। एक विधायक वाली राजद का एक मंत्री है और 16 विधायक वाली कांग्रेस के चार मंत्री हैं। लेकिन मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की कोई आजादी नहीं है। राज्य सरकार कई तरह के आरोपों में फंसी है। मुख्यमंत्री के नाम से पत्थर माइंस की लीज की गई थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री के विधायक भाई और पत्नी के ऊपर माइंस और जमीन लेने के आरोप हैं। मुख्यमंत्रियों के करीबियों के खिलाफ जांच चल रही है और फर्जी कंपनियों को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके बावजूद सरकार को जिम्मेदार बनाने के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की ओर से कई बार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की गई लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन को फॉर गारंटेड मान कर चल रहे हैं। वे प्रदेश के हाई प्रोफाइल प्रभारी को भी कोई खास तवज्जो नहीं देते।

महिलाओं में मोटापा और कुपोषण बढ़ा रहा समस्या, चिंता पैदा कर रहे हैं ये आंकड़े

खानपान समेत विभिन्न कारणों के चलते मोटापा आज भले ही अमीरी की निशानी न रह गया हो मगर कुपोषण का कारण आज भी गरीबी ही है। भारत में कुपोषण के कारण जहां पचास प्रतिशत से अधिक महिलाएं कमजोर, बौने और जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को जन्म दे रही हैं और रक्त अल्पता की बीमारियों का सामना कर रही हैं वहीं देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं के लिये मोटापा गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्या बन रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सवेक्षण-5 के अनुसार अधिकांश राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा महिलाओं में 21 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत और पुरुषों में 19 प्रतिशत से बढ़ कर 23 प्रतिशत हो गया है। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप (34-46 प्रतिशत) में एक तिहाई से अधिक महिलाएं अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। जबकि देश में मातृ और बाल कुपोषण और रक्ताल्पता का स्तर चिंताजनकस्तर तक पहुंचा है और इसके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा महिलाओं में 21 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत और पुरुषों में 19 प्रतिशत से बढ़ कर 23 प्रतिशत हो गया है। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप (34-46 प्रतिशत) में एक तिहाई से अधिक महिलाएं अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।

अधिक वजन होने या मोटापा होने से जोड़ों और कार्टिलेज पर अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है. मोटे लोगों को मेटाबोलिक सिंड्रोम के कारण कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जो हृदय रोग, मधुमेह और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है। इसे अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका संबंधी रोगों के कारक के रूप में भी शामिल किया गया है।

मोटापा बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है लम्बे समय तक जितनी कैलोरी आप रोज खाते हैं, उससे कम दैनिक गतिविधि और व्यायाम में बर्न करते हैं। समय के साथ, ये अतिरिक्त कैलोरी जमा हो जाती हैं और वजन बढ़ने का कारण बनती हैं। लेकिन इनके अलावा भी मोटापे के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं।

शोधपत्र के अनुसार दक्षिण में मोटापे की समस्या उच्चतम 46.51प्रतिशत और पूर्वोत्तर में सबसे कम 32.96प्रतिशत पाई गई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोटापा पाया गया।

मोटापे की व्यापकता 40.3 प्र.श. तक होने का दावा

इंडियन एकैडमी ऑफ न्यूरो साइंस के जर्नल ''एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंस'' में मई 2021 में छपे मुरली बैंकटराव आदि के शोध पत्र के अनुसार यद्यपि भारत में ओबेसिटी या मोटापे का अब तक कोई सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी शोधार्थियों ने देशभर से 1,00,531 वयस्कों के नमूनों के आधार पर निष्कर्स निकाला भारत में मोटापे की व्यापकता 40.3प्रतिशत है। यह व्यापकता एक समान नहीं है। शोधपत्र के अनुसार दक्षिण में मोटापे की समस्या उच्चतम 46.51प्रतिशत और पूर्वोत्तर में सबसे कम 32.96प्रतिशत पाई गई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मोटापा पाया गया। महिलाओं में 41.88 प्रतिशत तथा पुरुषों में 38.67प्रतिशत पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 36.08 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 44.17 प्रतिशत पाया गया। और 40 से कम (45.81प्रतिशत के मुकाबले 34.58 प्रतिशत) की तुलना में अधिक अधिक शिक्षित लोगों में 44.6 प्रतिशत और अशिक्षित में 38 प्रतिशत पाया गया।

जयसिंह रावत

मिला जुला

यूक्रेन में युद्ध से घटती आपूर्ति से प्रभावित देशों को गेहूं भेजना जारी

दुनिया में कितनी है पीएम मोदी की विश्वसनीयता, समझिए कैसे यह गेहूं से तय होने जा रहा

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा का बढ़ता खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पहेली में धकेलने को तैयार है। यूक्रेन में युद्ध से घटती आपूर्ति से प्रभावित देशों को गेहूं भेजना जारी रखें या उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए घर पर इसका भंडारण करें।

भीषण गर्मी ने दक्षिण एशियाई देशों में गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकार को निर्यात प्रतिबंधों पर विचार करना पड़ा है।

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि उसे अभी तक गेहूं के निर्यात को नियंत्रित करने का कोई मामला नहीं दिखता है, यह एक ऐसा सवाल है जो आगे भी उठेगा और पीएम मोदी व उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक प्रभाव डालेगा।

पीएम मोदी के सामने है यह दुविधा

पीएम मोदी के सामने एक भरोसेमंद वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने का सवाल है। साथ ही उन्हें रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति के बारे में घरेलू स्तर पर निराशा को भी देखना है। यह ऐसा मुद्दा जिसने पिछली सरकार को गिरा दिया और सत्ता में उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, भंडार, निर्यात की समीक्षा की

पीएम मोदी ने बीते गुरुवार को गेहूं की आपूर्ति, भंडार और निर्यात की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि भारत को खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के पक्के स्रोत के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी मानवता पर संकट आता है तो भारत समाधान लेकर आता है।

भारत को गेहूं का स्थायी निर्यातक बनने की उम्मीद

दुनिया के शीर्ष खरीदार मिस्र ने हाल ही में भारत को गेहूं के आयात के स्रोत के रूप में मंजूरी दी है। पिछले महीने खाद्य और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत गेहूं का एक स्थायी निर्यातक बनने की उम्मीद करता है, जो इस साल 15 मिलियन टन शिपिंग करेगा, जबकि 2021-22 में यह लगभग 7.2 मिलियन था।

गोयल ने कहा कि अधिकारी नियमों में ढील देने के लिए विश्व व्यापार संगठन पर जोर दे रहे हैं ताकि भारत राज्य के भंडार से निर्यात कर सके।

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भगवंत मान से मिलेंगे नवजोत सिद्धू

चंडीगढ़: ट्वीट कर सिद्धू ने बताया कि वह राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार पर चर्चा के लिए मान से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि पंजाब का फिर से ढर्रे पर लाने का काम केवल एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। नवजोत सिंह सिद्धू कब और किधर पलटी मार दें कोई नहीं बता सकता। उनकी इस आदत से कांग्रेस नेतृत्व तक आजिज आ गया था। तभी उन्हें PPCC चीफ की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। एक दिन पहले तक वो बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान और केजरीवाल पर निशाना साध रहे थे।

एक नजर

शाहीन बाग में दंगा कराना चाहते हैं भाजपा नेता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के बुलडोजर पहुंचे हैं और इसे लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मुख्य सड़क को जाम करके खड़े हैं और बुलडोजरों के आगे आ गए हैं। इस बीच लोगों को हटाने के लिए फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा है कि अतिक्रमण को हटाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन माहौल गर्मा गया है और आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्षद वाजिद खान ने भाजपा पर दंगे की साजिश का आरोप लगाया है। वाजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मुख्य रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। इसे रोड नंबर 13 बोलते हैं। भाजपा ने यहां विकास के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन चुनाव टलने के बाद राजनीति को चमकाने के लिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता वाजिद खान ने कहा कि भाजपा के नेता चाहते हैं कि शाहीन बाग में दंगा हो जाए। मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान भी पहुंचे हैं और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का विरोध किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके से नेताओं और लोगों को हटाने में जुटा है। एमसीडी के अधिकारियों ने कहा कि लोगों ने भी स्ट्रक्चर अपने दायरे से बाहर बना रखा है, उसे हटाया जाएगा।

हिमाचल ने सील की सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं

हिमाचल। हिमाचल की भाजपा सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी हैं. इसके साथ पुलिस विभाग को चेकिंग करने के आदेश दिए हैं. डीजीपी की ओर से कहा गया है कि राज्य में आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जाए. इसके साथ ही रात्रि गश्त भी तेज कर दिया गया है. बता दें कि एक दिन पहले धर्मशाला में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटके मिलने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. विधानसभा परिसर के गेट और चारदीवारी पर खालिस्तान समर्थक चित्र भी बनाए गए थे. उसके बाद से अंतरराज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है. हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए और कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच सुनिश्चित की जाए. बिना जांच के कोई वाहन राज्य की सीमा में प्रवेश ना कर पाए. पुलिस विभाग को भेजे संदेश में कहा- पड़ोसी राज्यों में खालिस्तानी तत्वों की घटनाएं सामने आई हैं. इसके अलावा, 11 अप्रैल को ऊना जिले में खालिस्तानी बैनर बांधने का मामला सामने आया था. डीजीपी ने कहा कि हाल ही में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के बैनर लगाने की घटना सामने आई है. साथ ही आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए 6 जून 2022 को मतदान तिथि की घोषणा की है.

खालिस्तानी फ्लैग लगाए जाने के बाद अलर्ट

केंद्र का बड़ा फैसला

देशद्रोह कानून पर होगा पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट से की यह अपील

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। केंद्र ने कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में जब कि

देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, गुलामी के समय में बने देशद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है, देशद्रोह कानून को लेकर जताई जाने वाली आपत्ति का भारत सरकार को ज्ञान है। कई बार मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठाए चजाते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखना होना चाहिए। एफिडेविट में आगे कहा गया, अब समय आ गया है कि आईपीसी की धारा 124 के प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए।

भारत से रूस तक बनाई रोड, लाल सेना की बचाई जान

मास्को/नई दिल्ली। दूसरे विश्वयुद्ध में हिटलर की नाजी सेना के खिलाफ कई वर्षों तक चली भीषण जंग में सोवियत संघ के शानदार जीत पर रूस आज विजय दिवस मना रहा है। रूस के करीब 11 हजार सैनिक राजधानी मास्को में विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। यह परेड ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन की जंग में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बुरी तरह से फंसा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रण किया है कि वह यूक्रेन की सेना को भी हिटलर की तरह से पराजित करके ही दम लेंगे। दूसरे विश्वयुद्ध में सोवियत संघ की सेना भी यूक्रेन की जंग की तरह से ही फंसी हुई थी और जर्मन तानाशाह हिटलर के भीषण हमलों से कराह रही थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क भ्रष्टाचार की चढ़ी भेंट

सड़क बनाने के नाम से अनियमितताएं छः करोड़ रुपए की लागत से बन रही नाली एवं सड़क

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

जिले के साजा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत भनौरा और ठेलका डोगीतराई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सीसी रोड और नाली जिसमे कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं।

जी हां बता दे की ग्रामीणों में आक्रोश ठेकेदार के दुर्व्यवहार और घटिया काम को लेकर मीडिया से लगाई गुहार मटेरियल में ठेकेदार की लीपापोती से ग्रामीण यह मान रहे हैं कि इस तरह से काम किया गया तो रोड पूरे पांच साल नहीं टिक पाएगी। क्योंकि रोड और नाली कार्य प्रारंभ की तिथि 15 मई 2020 था कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 14 जनवरी 2022 है लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी कार्य अभी आधा तक पूर्ण नहीं हुआ है और ग्राम भनौरा में घटिया नाली निर्माण वह भी आधा अधूरा किगई है जो पूरी तरह से टूट चुकी है ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे कभी भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी हुई है। वही गांव के पंच और सरपंच ने बताए कि गांव में कई बार बच्चे खेलते-खेलते नाली में तक गिर चुके हैं और काफी चोट आई हुई थी और तो और गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है बच्चे को साजा स्वास्थ्य केंद्र लेजाना पड़ा था! हालांकि अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है मामले की जानकारी ठेकेदार को दी गई थी। लेकिन उसका कहना है कि मुझे क्या करना तुम गांव वाले कौन होते हो मैं जब चाहूं काम करूं या ना करूं बिना बॉल्डर और कुटाई के साथ करोड़ों रुपए की लागत से रोड का निर्माण कराया जा रहा है। जिससे यह सड़क गारंटी पीरियड तक नहीं चल सकेगी।

करोड़ों से होगा निर्माण ठेलका से भनौरा से डोगीतराई तक करीब छह करोड़ रुपए की लागत से इस रोड और नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी रोड का काम 5 साल की रहती है गारंटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क की निर्माण कंपनी पांच साल की गारंटी देती है। जिसके बाद ही संबंधित ठेकेदार को लागत राशि आवंटित की जाती है। लेकिन देखा गया है कि क्षेत्र में कई गांवों में इस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनमें गुणवत्ता का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन ठेकेदार विभाग के अधिकारियों व इंजीनियरों से मिलकर सड़कों को पास करा लेते हैं। मिट्टी के ऊपर सीधे मटेरियल डालकर रोड का निर्माण शुरू करा दिया जाता है। जबकि एस्टीमेट के अनुसार पहले मिट्टी पर छिड़काव करके बेस तैयार किया जाएगा। फि र बॉल्डर, गिट्टी डालकर कुटाई की जाएगी। इसके बाद ही रोड पर सीसी का काम किया जाना है। मगर इन सभी को ध्यान में नहीं रखते हुए अनियमितता के साथ कार्य किया जा रहा है। तो अधिकारियों को सड़क की जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठेकेदार का कहना था कि लॉक डाउन होने के कारण और मटेरियल में बढ़ोतरी के कारण कार्य नहीं होपाया है। और जगह-जगह पानी की जमाव होने के कारण कार्य में समय लगा लेकिन अब एक माह के भीतर कार्य पूर्ण हो जाएगा अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद क्या 1 माह के भीतर ठेकेदार काम पूर्ण कर पाती है या नहीं।

एक नजर

सफलता की कहानी

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला में अब तक 402 पारा, महोहल्ले एवं टोलों में सोलर ड्यूल पंप किया गया स्थापित

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला में अब तक 172 ग्राम पंचायतों के कुल 402 पारा, महोहल्ले एवं टोलों में पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप की स्थापना की जा रही है। यह योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं क्रेडा विभाग द्वारा लगाया जाता है। इस योजना के द्वारा प्रति संयंत्र से 40-50 परिवारों को शुद्ध पेयजल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ताकि ग्रामों में निवास कर रहे परिवारों को पानी की समस्या दूर हो तथा उन्हे शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में मनोरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत ओरडीह के मेनबस्ती में जल जीवन मिशन आंतर्गत 48 परिवारों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है। अब परिवारों की पेयजल की समस्या दूर हो गई और उन्हें शुद्ध पेयजल मिल रहा है।

पुलिस जवान संदीप साहू ने जरूरतमंदों के लिए शीतल पेयजल की खोली प्याऊ

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

बदलते जमाने के साथ लोगो की जरूरते भी बदलने लगी है। पहले लोग जगह-जगह प्याऊ घर खोलते थे नगर पालिका का शहर बेमेतरा में एक भी प्याऊ घर नहीं खुला था। लोग पानी के लिए भटक रहे थे। गला तर करने पानी खरीदकर पीना पड़ रहा था। समाजसेवी संस्थाओं के स्थाई प्याऊ बंद पड़े हैं। गर्मी शुरू होते ही लोगों के कंठ सूखने लगे हैं। शुरूआत में ही पड़ रही तेज गर्मी से लोगों की प्यास बढ़ गई है। गर्मी में अक्सर सड़क किनारे के प्याऊ ही लोगों का सहारा बनते हैं। नगर पालिका ने अब तक शहर में प्याऊ खोलने की योजना भी नहीं बनाई है। ऐसे में बेमेतरा सिटी कोतवाली के सामने जरूरतमंदों के लिए शहर में इस वर्ष पहला प्याऊ घर खोला गया है। इन दिनों गर्मी के चलते राहगीरों को पानी की काफी समस्या हो रही थी इसे देखते हुए बेमेतरा के पुलिस जवान संदीप साहू के मार्गदर्शन में समाज सेविकाओं ने मिलकर प्याऊ घर की व्यवस्था की वही प्रथम दिन में ही एक भिक्छुक दिव्यांग जो पानी के लिए भटक रहा था उसे संदीप साहू ने बुलाकर अपने हाथों से मीठी शरबत पिलाई देखा जाए तो पानी की किल्लत बढ़ी हुई है। राहगीरों को मिलेगी अब निजात।

पोड़ीबहार तालाब की सफाई में वार्ड पार्षद ने साथियों के साथ किया श्रमदान

कोरबा । नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 29 पोड़ीबहार स्थित तालाब की सफाई के कार्य में वार्ड पार्षद व मेयर इन काउंसिल सदस्य प्रदीपराय जायसवाल ने अपने साथियों एवं वार्डवासियों के साथ श्रमदान दिया तथा तालाब की सफाई का कार्य किया। तालाबों के संरक्षण एवं उनकी स्वच्छता की दिशा में प्रशंसनीय पहल करते हुए पार्षद श्री जायसवाल ने स्वप्रेरणा से पोड़ीबहार तालाब की साफ-सफाई की, जो प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी एवं उनके स्टाफ के साथ ही वार्ड के युवागण राजू गोड़, दिनेश कुमार, किशन केवट, कमलेश बंजारे, टुकेश जांगड़े, लकेश्वर चौहान, धनंजय चौहान, अनुप कुमार, राकेश कुमार, भरतलाल, राजकुमार, बद्रीप्रसाद, निरंजन, राजू कुमार, सचिन कुमार, गोपाल, कोको कुमार आदि के साथ अन्य युवाओं ने अपना श्रमदान देकर साफ-सफाई का कार्य किया।

माता-पिता के ऋण से कभी मुक्त नही हो सकती संताने-डॉ. रश्मि सोनकर

लायंस वृद्धाश्रम में मातृ दिवस मनाया प्रबल स्त्री फाऊंडेशन ने

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

धरती में जीवन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जन्मदाता का जीवन होता है। माता-पिता के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ऐसे मे जो व्यक्ति आपको इस पृथ्वी पर लाते हैं। उनका कर्ज हम पूरा नहीं कर सकतेए दुर्भाग्य जनक बात है वर्तमान परिस्थिति मे सैटल हो जाने के बाद बेटे बेटियां अपने वृद्ध माता पिता को किनारे कर देते है, ये सबसे बड़ी सामाजिक विसंगति है। इस पर सारे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के प्रारंभ होने से हमारे सक्षम होने तक माता-पिता के अतुलनीय मेहनत का योगदान होता है, जिसे किसी भी स्तिथि मे भुलाया जाना निंदनीय है। एक ओर हम अपने समाज के तरक्की की बात करते है, इस समाज की आधारशिला रखने वाले मातापिता के संबंधों को सबसे पहले दरकिनार कर देते है। प्रबल स्त्री फाऊंडेशन ऐसे सभी माता-पिता जो अपने संतानों से वंचित है उनके सहयोग और उनके सेवा के लिए सदा तत्पर है। उक्त आशय से प्रबल स्त्री फाऊंडेशन की अध्यक्ष डॉ रश्मि सोनकर लायंस वृद्धाश्रम मनेंद्रगढ़ मे मातृ दिवस का कार्यक्रम सभी बुजुर्गो के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। और समाज के सभी वर्ग से आशा की है कि भारतीय संस्कृति में माता-पिता देवतुल्य है उनका सम्मान हमारा धर्म और कर्तव्य है। सभी सदस्यों ने अपने अपने इच्छानुसार खाने का समान, फल और साड़ी भेंट की, कार्यक्रम में सबसे पहले बुजुर्गों के पैर धोकर, आरती व पुष्पवर्षा का कार्यक्रम हुआ, इस बीच सभी बुजुर्गो ने अपने आशीर्वाद वचन मे सभी को धन्यवाद कहाद्य कार्यक्रम में डॉ रश्मि सोनकर, शीला सिंह, प्रतिमा प्रसाद, जया कर, महेश्वरी सिंह, मीनु सिंह, सुनिता नेताम, सविता बुनकरए सविता गुप्ता, नेहा कोठारी, रुबी लाल, अनिता मिश्रा, आकाश दुआ, गौरव मिश्रा, विवेक तिवारी मौजूद रहे व कार्यक्रम को सफल बनाया।

आयुक्त ने आदेश जारी कर भवन निर्माण अनुमति विभाग में किया फेरबदल

अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला बनाए गए निगम के भवन अधिकारी, बदले गए शाखा के इंजीनियर व लिपिक

कोरबा । आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आदेश जारी कर नगर पालिक निगम कोरबा के भवन निर्माण अनुमति विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला को भवन अधिकारी का प्रभार सौपा गया है, वहीं कार्यपालन अभियंता एम.एन.सरकार को भवन अधिकारी के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार कार्यपालन अभियंता अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला अब निगम के नए भवन अधिकारी होंगे। आयुक्त श्री पाण्डेय ने एक अन्य आदेश में भवन निर्माण अनुमति शाखा में पदस्थ इंजीनियर व लिपिकीय कार्य देख रहे कर्मचारियों में भी बदलाव किया है। हृदयराम बघेल सहायक अभियंता अब अपने कार्यो के साथ-साथ भवन निर्माण अनुमति शाखा के कार्य को देखेंगे, वहीं श्रीमती गुलिस्ता साहू उप अभियंता को भवन निर्माण अनुमति शाखा से स्थानांतरित कर कोरबा जोन में पदस्थ किया गया है। अरविंद वानखेड़े सहायक ग्रेड-02 को स्थापना शाखा से भवन निर्माण अनुमति शाखा में लाया गया है, वहीं कम्प्यूटर आपरेटर अजय शुक्ला को भवन निर्माण अनुमति शाखा से स्थानांतरित कर स्थापना शाखा में पदस्थ किया गया है, साथ ही भवन निर्माण अनुमति शाखा में कार्य कर रहे स्वच्छता पर्यवेक्षक शैलेन्द्र नामदेव को स्वच्छता शाखा कोरबा जोन में स्थानांतरित किया गया है।

सहकारी समितियों में अनाधिकृत रूप से झाइम खाद की बिक्री से किसानों में नाराजगी

क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी से शिकायत कर विरोध में आवाज बुलंद करने की रखी मांग

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

जिले की सहकारी समितियों में अमानक व अनाधिकृत रूप से झाइम खाद के बिक्री की लगातार शिकायत मिल रही है। कृषि विभाग की कार्रवाई के बावजूद अनाधिकृत खाद की बिक्री जारी है। उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी समितियों में मार्कफेड से खाद और बीज निगम से आपूर्ति किए गए बीज की अधिकृत रूप से बिक्री की जाती है। लेकिन जिले के लगभग सभी समितियों में झाइम खाद की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इस सम्बंध में बेमेतरा विधानसभा के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी से

शिकायत कर निराकरण की मांग की है। किसान नेता ने कहा कि कृषि विभाग की ओर से जिन समितियों में कार्रवाई की गई है। वहां खाद को लेकर समितियों के पास से कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। किसानों को अमानक खाद खपाई जा रही है। सहकारी समितियों में झाइम खाद की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने किसान नेता योगेश तिवारी क्षेत्र के किसानों के साथ कृषि अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे।

कृषि विभाग ने 3 समितियों से 1500 बाल्टी झाइम खाद की जप्त

किसान नेता ने कहा कि अनाधिकृत रूप से खाद बेचने का काम समितियों में किया जा रहा है। कृषि विभाग की टीम ने सेवा सहकारी समिति चंदनूए खंडसरा और उमरिया में में अनाधिकृत रूप से बेची जा रही झाइम खाद की लगभग 1500 बाल्टी खाद जब्त किया है। जैविक खाद के नाम पर किसानों को अन्य खाद भी दिया जा रहा है। इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी है। समिति चंदनू और खंडसरा में ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जब औचक निरीक्षण किया गया। जिसमे किसानों की शिकायत सही मिली। कोमल साहू ग्राम नेवनारा, देवकुमार साहू ग्राम कुसमी, रघुवीर साहू ग्राम आंदु, दिलरहण सिन्हा नवागांव ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को सेवा सहकारी समितियों में किसानों को जबरदस्ती झाइम खाद थमाया जा रहा है। इसके लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। वही इस खाद की रसीद भी नहीं दी जा रही है। स्पष्ट है कि झाइम खाद को अनाधिकृत रूप से बेचा जा रहा है। लगातार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से अवैध कृत्य कर रहे हैंए कर्मियों के हौसले बुलंद हैं।

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर

लाटरी के माध्यम से 40 विद्यार्थी हुए चयनित

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर में कक्षा पहली के 40 सीट में प्रवेश हेतु आवेदन मंगा थे। जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद की अध्यक्षता में गठित चयन समिति एवं पालकों की उपस्थिति में आज कक्षा पहली में प्रवेश हेतु लाटरी ड्रा किया गया। लाटरी ड्रा में के समय आवेदित लगभग सभी पालक उपस्थित थे। प्रवेश हेतु सभी पालकों में उत्साह देखा गया और लाटरी में अपने बच्चों के नाम आने से बहुत ही उत्साहित दिखे। प्रवेश के लिए शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया गया।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु आवेदन ऑफलाईन तथा ऑनलाइन माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार महतारी दुलार योजना अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को

विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया गया। कक्षा 1 में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया गया। बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूध्द प्रवेश दिया गया। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लाटरी सिस्टम से दिया गया। उपर्युक्त सभी वर्गों से अधिक संख्या में आवेदन आने से सभी वर्ग हेतु लाटरी से ही चयन किया गया। चयनित छात्र-छात्राओं की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। कक्षा 2 से 12 तक बढ़े हुए सीटों का प्रवेश फार्म 9 मई से 20 मई तक दिया जाएगा।

कांग्रेस चुनावी वायदे से न मुकरे,छत्तीसगढ़ बिजली ठेका कर्मचारी कल्याण संघ का अनुरोध

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

छग. विद्युत ठेका कर्मचारी कल्याण संघ कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने का आग्रह और निवेदन करता है।कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में अनियमित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मंच में आकर कहा था।

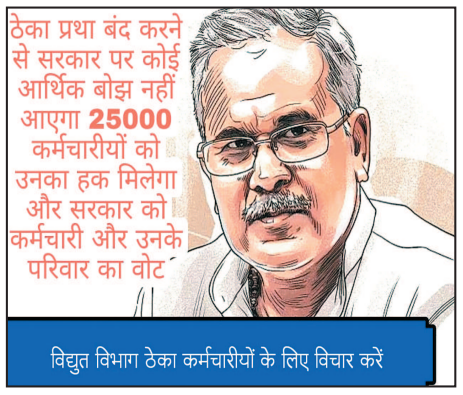

कांग्रेस को वोट दो कांग्रेस की सरकार बनाओ सरकार बनते ही 10 दिन में ठेका प्रथा बंद कर विभाग में समायोजन नियमितीकरण किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित को नियमित, ठेका प्रथा बंद कर विभाग में समायोजन करने का वादा किया था। लेकिन आज तीन साल हो गए वादे पूरा नही हुआ। डिसटीब्यूशन,ट्रांसमिशन, जनरेशन के पच्चीस हजार विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी नाराज और अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे हैं ठेका प्रथा बंद कर विभाग में समायोजन कर डायरेक्ट पेमेंट करे नियमितीकरण करे कांग्रेस सरकार जो कहती है उसे पूरा करती हैं तो क्यों नहीं हुआ ठेका प्रथा बंद कर विभाग में समायोजन नियमितीकरण का वादा पूरा भूपेश सरकार है तो भरोसा है। कब मिलेगा न्याय ठेका प्रथा जैसे गुलामी से मुक्ति, ठेकदारों द्वारा टाइम पर ना वेतन ना ईपीएफ की राशि, बोनस नहीं दिया जा रहा है वेतन काटकर डायरेक्ट शोषण कर रहे हैं। लाखो करोड़ों का टेंडर निकालकर सरकार ठेकदारों को डायरेक्ट लाभ दे रहे हैं। और ठेका कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ठेका कर्मचारी विभाग का काम डायरेक्ट कर रहे हैं तो सरकार डायरेक्ट पेमेंट क्यों नही कर सकता। बीच में बिचौलियों को क्यों भर दिया गया है लाइन एक्सीडेंट में कई ठेका कर्मचारियों की जान गई। ना बीमा ना मुवाअजा ना अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जाता है। ठेका कर्मचारियों की जान की कोई कीमत नहीं है। कई बार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सरकार को वादा याद दिलाया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ सरकार ठेका कर्मचारी की मांगे और वादे को पूरा करे। विद्युत ठेका कर्मचारी कल्याण संघ महामंत्री जितेंद्र कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश उपाध्यक्ष नोहर टंडन, चुम्मन साहू,जिला अध्यक्ष किशन लाल साहू, ऋ षि निषाद, टीकाराम ठाकुर आदि पच्चीस हजार विद्युत ठेका कर्मचारी सरकार से मांग पूरा करने का आग्रह और निवेदन करता है।

घनी आबादी के बीच जीबीटी मोबाइल टावर, विरोध में उतरे वार्डवासी

उदासीनता के विरुद्ध जनता आंदोलन के मूड में

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुन्द्र।

स्थानीय वार्ड क्रमांक 06 में दिलीप सिंह जूदेव टाउन हाल के पीछे रिलायंस जियो इन्फ ॅटेल लिमिटेड द्वारा जीबी टी. मोबाइल टावर लगाने का कार्य वार्डवासियों के पुरजोर विरोध के बाद भी प्रगति पर है। मना करने पर कार्य ठेकेदार द्वारा विरोधकर्ता वार्डवासियों को ही झूठे केस में फंसवा देने की धमकी ही जा रही है।

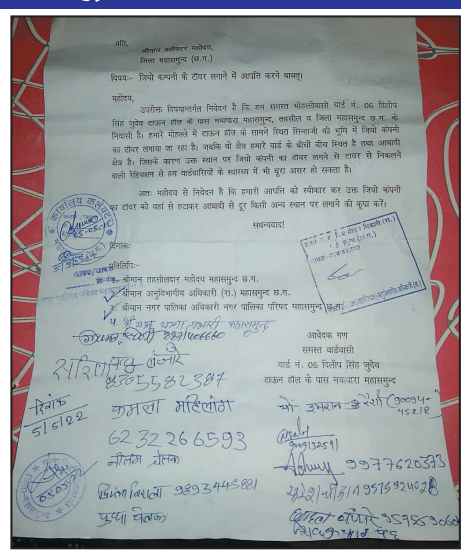

जिससे नाराज वार्डवासियों ने आज 09 मई को पुन: संसदीय सचिव सहित जिला प्रशासन से शिकायत करते हुये मोबाईल का काम न रुकने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञातव्य है किए उक्त मोबाइल टावर दो साल पहले वार्ड 6 में ही धीरज सरफ राज के मकान के पीछे नेतराम देवांगन की जमीन पर लगाया जा रहा था। जिसे नागरिक विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद वार्ड 09 के रेलवे कालोनी में इसे स्थापित करने का प्रयास भी नागरिकों के तीव्र विरोध से संभव नहीं हो पाया। तीसरी कोशिश में यह टावर वार्ड नं.10 में पूर्व पार्षद शकील खान के मकान की छत पर लगाया जाना लगभग तय था। लेकिन यहां भी वार्डवासी विरोध में उतर आये तो अब पुन: इसे वार्ड न 6 में ही परिवर्तित स्थान पर लगाने जाने युद्ध स्तरीय प्रयास किया जा रहा है। जबकि यहां के नागरिक भी बीते दो माह से मोबाईल टावर लगाने से मना कर रहे हैं। सभी के स्वास्थ्य पर प्रतिभूत प्रभाव पढ़ने की चिंता है। बीते 5 मई को भी विधायक सहित कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार,थाना प्रभारी और नगर पालिका परिषद आपत्ति पत्र पत्र प्रस्तुत कर मोबाईल कम्पनी को प्रदाय अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की लिखित मांग की गई थी जिस पर उचित कार्यवाही का मौखिक दिया गया था। लेकिन यथार्थ में कोई कार्यवाहीं नहीं हुई और आज जब स्ट्रक्चर खड़ी करने ढलाई कार्य की शुरुवात हुई तो ठेकेदार फिर अडियल पना दिखाते वार्डवासियों को धमकाने लगा। इसके बाद मुहल्ले वाले भी लामबंद हो गये। सोमवार को विधायक विनोद चंद्राकर से भी मिले और निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई। वार्डवासियों की शिकायत पर कार्यवाही ना होने से वे आंदोलन के मूड में है। संभवत वार्डवासी कल मंगलवार से निर्माण स्थल पर आंदोलन कर सकते हैं। वार्डवासी में इमरान कुरैशी, सुरेश चौहान, बादल बंजारे, कमला महिलांग नीलम महिलांग, प्रियंका निराला सहित अन्य का कहना है किए जब उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसकी शिकायत प्रशासन से की गई है तो मामले के निराकरण होने तक निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। उनका कहना है कि निर्माण बंद नहीं होने की स्थिति में वे मंगलवार से आंदोलन के लिए मजबूर है।

एक नजर

अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत जनसम्पर्क

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुन्द।

भाजपा संगठन द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत भाजपा ग्रामीण मण्डल महासमुन्द लोहारडीह शक्तिकेन्द्र के ग्राम सिंघी,लोहरगांव,और नायक बांधा में समयदानी विस्तारक पार्षद मीना वर्मा, शहर मण्डल मंत्री महेंद्र सिका, पार्षद हफीज कुरैशी ने शक्तिकेन्द्र के प्रभारी हेमलाल चंद्राकर,संयोजक कृष्णकुमार पटेल,सह संयोजक भगतराम निषाद,शोसल मीडिया विस्तारक बलदाऊ निर्मलकर की उपस्थिति में बूथ अध्यक्ष, पालक सहित बूथसमिति के सदस्यों की बैठक लेते हुए बूथों से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की समीक्षा की गई।

बारंगाव की उभरती खिलाड़ी डाली का नेशनल हाकी प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम में हुआ चयन

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

कम संसाधनों के बावजूद बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बारंगाव की उभरती खिलाड़ी डाली निषाद का राष्ट्रीय सब जूनियर हाकी प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम में चयन हुआ है। अपने खेल के दम पर डाली गांव और जिला का नाम रोशन कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि 11 से 22 मई तक हॉकी इंडिया 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन इंफाल मणिपुर में हो रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए डाली का सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की हॉकी टीम के लिए चयन हुआ है। डाली ने बताया कि उसे हॉकी खेलने का बेहद शौक है और देश के लिए हॉकी खेलकर अपने परिवार और राज्य दोनों का नाम रोशन करना चाहती हैं। बारगांव में पीटीआई टीचर तुलसी साहू के आने के बाद स्टूडेंट सुबह शाम प्रेक्टिस करते थे। सबसे पहले एक हफ्ता कैंप राजनांदगांव में था। जहां खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। डाली ने अपने चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अपनी टीम की जीत के लिए जीजान से खेलेंगी। गांव की बालिका का नेशनल प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम में चयन होने पर हर्ष जाहिर करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शुभम वर्मा और जनपद अध्यक्ष हीराबाई वर्मा ने कहा कि कम संसाधन के बावजूद डाली का चयन गांव समेत बेरला ब्लाक के अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। डाली ने अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत खेल प्रशिक्षक तुलसी साहू के मार्गदर्शन में राज्य की टीम में जगह बनाने में सफलता पाई है। डाली का चयन जिले के लिए गौरव की बात है।

अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार

नगरी । कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार के अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत नगरी मंडल के शक्ति केंद्र अमाली ग्राम अमाली बूथ क्रमांक 158 में दस दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का रुपरेखा तैयार किया गया। जिसमें शक्ति केंद्र प्रभारी गुरु प्रसाद साहू, बूथ अध्यक्ष दीनदयाल सेन, पूर्व सरपंच अमर सिंह ध्रुव, आशीष नाग, पेमन साहू,चम्मन नाग, राजाराम ध्रुव,बेनू राम ध्रुव उपस्थित हुए।

महापौर ने किया आमजन से अपील सरकार तुहर द्वार शिविर का उठाएं लाभ

11 मई को साड़ा कन्या स्कूल टी.पी.नगर में वार्ड क्र. 01 से वार्ड क्र. 16 तक के लिए लगेगा समाधान शिविर

कोरबा । महापौर राजकिशोर प्रसाद ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण कराए जाने के उद्देश्य से शासन-प्रशासन द्वारा आयोजित होने जा रहे '' सरकार तुहर द्वार '' शिविरों का लाभ उठाएं, शिविरों में पहुंचे तथा अपनी समस्याओं का निराकरण पाएं।

महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपील करते हुए कहा है कि 11 मई को निगम के कोरबा व टी.पी.नगर जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्र. 01 से वार्ड क्र. 16 तक के लिए समाधान शिविर का आयोजन साडा कन्या स्कूल टी.पी.नगर में किया गया है, इस शिविर में नगर पालिक निगम सहित जिले के समस्त 22 विभागों के काउंटर स्थापित होंगे, जहाँ पर संबंधित विभागों को अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हुए नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निदान करेंगे। उन्होने कहा है कि इस हेतु पूर्व से ही तैयारी की जा रही है, अधिकारी कर्मचारी घर-घर पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं, इन आवेदनों का पंजीयन करते हुए विभागों के बीच आपसी समन्वय बनाकर इनका संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जा रहा है, आयोजित होने वाले शिविर में निराकरण संबंधी जानकारी लोगों को दी जाएगी।

ऑनलाइन खरीदे गए 20 चाकू बरामद

पुलिस की युवाओं और नाबालिकों पर कड़ी नजर

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

अभी हाल के दिनों में यह देखने में आ रहा था कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है। जिनके संबंध में जानकारी हुई कि ऑनलाइन वेबसाइट आदि अन्य साइट के माध्यम से चाकू मंगा कर कुछ युवकों द्वारा या नाबालिगों द्वारा उसे अवैध रूप से अपने पास रख कर अपराधिक गतिविधियां की जा रही है।

इस पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में थाना कोतवाली व साइबर सेल की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट शॉपक्लूज, स्नैपडील के माध्यम से जिनके जिनके द्वारा भी उक्त बटन की चाकू,धारदार चाकू, पेन चाकू, या अन्य प्रकार के चाकू मंगा, हैं और जिन्हें वह अवैध रूप से अपने पास रखे हैं उक्त वेबसाइट से उन सभी लोगों की जानकारी प्राप्त कर उनसे संपर्क स्थापित कर उक्त अवैध चाकू को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। जिसमें विधि सम्मत कार्रवाई थाना कोतवाली में की जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभी वर्तमान में केवल दो ही ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है फ्लिपकार्ट अमेजॉन व अन्य साईट से भी जानकारी प्राप्त कर जिले में जितने भी ऑनलाइन चाकू डिलीवरी हुई है सभी जिन्होंने उन्हें मंगवाया है उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान पुलिस अधीक्षक महासमुंद विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर साहू व डीएसपी कल्पना वर्मा एके मार्गदर्शन में थाना स्टाफ व साइबर सेल टीम द्वारा की गई।

कलेक्टर ने फरसाबहार के एसडीएम, तहसील एवं जनपद कार्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण

राजस्व प्रकरणों का समय.सीमा में करें निराकरण-कलेक्टर

जोहार छत्तीसगढ़-जशपुरनगर।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज विकासखंड फरसाबहार के एसडीएम, तहसील एवं जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को शासकीय कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने एवं अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने एसडीएम, तहसील कार्यालय के विभिन्न कक्षों, शाखाओं, रिकार्ड रूम सहित पूरे परिसर का मुआयना करते हुए राजस्व अभिलेखों एवं दस्तावेजों के रख.रखाव का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और प्रभारी अधिकारियों को अपनी-अपनी शाखा के सभी रिकॉर्ड अद्यतन और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों का निराकरण की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकृत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही कार्यालय में आने वाले आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने एवं उसका निराकरण करने के लिए कहा।

कर्मचारियों को अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के दिए निर्देश

जिससे आम जनता को लाभान्वित किया जा सके। इसी प्रकार जनपद कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों से उनके दायित्व एवं कार्यों की जानकारी ली। कार्यालय में ग्रामीणों के लिए आवश्यक सुविधाएं रखने एवं उनकी समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यालय परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया और परिसर को स्वच्छ रखने तथा साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व फ रसाबहार मोहम्मद शबाब खान, जनपद सीईओ धनेश कुमार टेंगवार, सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

बैकुंठपुर एवं खड़गवां में बाल विवाह रोकने में बाल संरक्षण इकाई को मिली सफलता

जारी वर्ष में अब तक रोके गए 14 विवाह

जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया।

बाल विवाह जैसी समाजिक कुरीति को रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अभिलाषा बेहार के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम के द्वारा विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम कसरा एवं विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम उधनापुर में बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में आने पर मौके पर पहुंच कर औचक निरीक्षण कर दोनों विवाह रोकने में सफलता पायी गई। दोनों ही मामलों में प्रमाणपत्रों का निरीक्षण करने पर बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से कम पाए जाने पर दोनों पक्षों से निवेदन कर पंचनामा तैयार कर बाल विवाह रोका गया। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी, पर्यवेक्षक तथा किशोर पुलिस इकाई मौजूद थे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष टीम द्वारा कुल 14 बाल विवाह रोका गया है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता.पिता सगे संबंधी बराती एवं विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात् विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बालिग होने के पश्चात् विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु.मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णत: उन्मूलन हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं आमजनों से सहयोग प्राप्त करके ही इस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही की जा सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक नारायण बाईन, द्वारा आसमा पब्लिसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित कर मेडरमार कालोनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक -**नारायण बाईन,** फोन -फैक्स 07766299001, मो, 9479177711, 7489419194 Email-joharchhattisgarh@gmail.com, joharchhattisgarh@yahoo.co.in